Sir, the second issue is the perennial issue of very inadequate funding by the Government in terms of our GDP to premier research. And the third is, Sir, how do we translate the benefits of the research through patents to actual industry-use. There have been these three issues. Will the Minister kindly answer these questions and tell us how he seeks to address these shortcomings?

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the first question is, how the intellectual property created out of research is shared. I would like to inform the House that we have now a much more innovative system where the benefits of research, any intellectual property created and the resultant benefits, are shared. The scientist gets a proportional part; the lab gets a proportional part and the nation gets a proportional part. It is a very innovative system which is working very well. We shall further improve upon it and we are open to suggestions.

Then, Sir, the hon. Member has talked about the money that we spend on research. Currently, the nation spends about one per cent of its GDP on research. Seventy-five per cent of that money spent on research comes from the Government and only 25 per cent comes from the public sector. The hon. Prime Minister had publicly announced that we intended to double the spending on R&D from one per cent of the GDP to two per cent of GDP. I think, the recent slowdown has definitely affected it but we have objectives in place and our aspiration is to double the spending on R&D. But, through the House, I would like to appeal to the private sector that they must also increase their spending on R&D. They must employ more Ph.Ds so that we really become a nation which leads through innovations.

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सामाजिक दायित्व

*403. **श्री शिवानन्द तिवारी** :

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : ††

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा सामाजिक दायित्व निर्वहन के लिए किये जा रहे प्रयास आवश्यकता के अनुसार नहीं पाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और उससे संबंधित सेवाओं में कार्यरत लोगों में से 54 प्रतिशत लोग लम्बी बीमारियों व जीवन-यापन शैली से उत्पन्न बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ङ) क्या सरकार वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

†† सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) से (ड) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग ज्ञान से संबंधित एक उद्योग है तथा इसमें कर्मचारियों की भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाता है। कर्मचारियों की भर्ती योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग में रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन हुआ है तथा लगभग 2.2 मिलियन कार्मिकों को उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया है और अनुमानतः 8 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। उद्योग में 30% से अधिक कर्मचारी महिलएं हैं जो किसी भी अन्य औद्योगिक खण्ड से अधिक है और अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में शारीरिक विकार के बावजूद सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग में कार्य कर रहे लोगों की जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की घटना के बारे में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन इस संबंध में कोई विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार बीपीओ कम्पनियों में कार्य की परिस्थितियां संबंधित राज्य सरकारों के दुकान एवं स्थापन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अधिकांशतः विनियमित होती है। बीपीओ कर्मचारियों के कार्य समय का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित एवं कार्यान्वित उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा किया जाता है।

Social responsibility of IT industry

†*403. SHRI SHIVANAND TIWARI:††

SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the efforts being made by information technology industry for fulfilling social liability have not been found as per requirement;

(b) if so, the reaction of Government in this regard;

(c) whether it is also a fact that 54 percent of people working in information technology industry and allied services are suffering from chronic and life style related diseases;

(d) if not, the facts in this regard; and

(e) whether Government would issue any guidelines for improving the present condition?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) As per the National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), the IT - ITES industry is a knowledge industry and does not discriminate in recruiting employees. Employees are recruited on the basis of merit and competency. The IT - ITES industry has been a

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha

large generator of employment, with about 2.2 million professional directly employed by the industry and indirect job creation estimated at 8 million. Over 30% of the employees in the industry are women - higher than any other industry segment and a majority of the IT industry employs differently enabled people.

There have been a few reports about incidence of life style related diseases among IT -ITES employees. However, no reliable statistical data is available in this regard.

As per the Ministry of Labour & Employment, the working conditions in the BPO Companies are largely regulated by the provisions of the Shops and Establishments Act of the respective State Governments. The working hours of the BPO employees are governed by the provisions of said Act, enacted and implemented by the State Governments.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पिछले एक decade से Information & Technology Industry के development में भारी भूचाल आया है और आज देश की GDP में इसकी partnership लगभग 7 परसेंट हो चुकी है। इस इंडस्ट्री के विकास के लिए भारत सरकार ने एक तरफ Tax Holiday की रियायत दी हुई है और दूसरी तरफ दुनिया के Developed countries ने इसके development के लिए opportunities पैदा की हैं। आज भी इस उद्योग से संबंधित कंपनियां सीधे College Campuses में जाकर talented and young छात्रों को अपने यहां नौकरियां दे रही हैं। जैसी रिपोर्ट है कि इस उद्योग में काम करने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा employees अपनी health loose कर रहे हैं। इन हालातों में इस उद्योग के wider पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। आज हमें सोचना है कि Wealth या Health ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : सभापति जी, दोनों ही जरूरी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग को अपने लाभ का कम से कम 30 परसेंट अपने कर्मचारियों की health को गिरने से रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर खर्च करना होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की compulsory व्यवस्था कायम करने के लिए IT उद्योग को स्पष्ट निर्देश देगी, यदि नही, तो क्यों नहीं?

श्री सचिन पायलट : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं कि देश में जो IT Sector है, उसकी ग्रोथ पिछले वर्ष लगभग 13 प्रतिशत थी और दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बावजूद भी हमारे IT Sector ने बहुत अच्छा perform किया और आज हमारे यहां लगभग 22 लाख लोग ऐसे हैं, जो IT Sector से directly employed हैं और लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं, जो indirectly employed हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने उस रिपोर्ट का जिक्र किया है, मैं नही समझता कि किसी एक रिपोर्ट या किसी एक सर्वे को मापदंड बनाना ठीक होगा, क्योंकि आप जिस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में जो 22 लाख employees हैं, उनमें से केवल 36 employees का सर्वे किया गया था और वह voluntary disclosure था। मैं नही समझता कि हमें इस सीमित दायरे से इस चीज को देखना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से यह बात भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो IT Companies हैं, इस देश में बेहतरीन employment देने के लिए दुनिया भर में उनका नाम है। IT Sector में जो employees है, उनमें से लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं और 60 प्रतिशत कंपनियां differently enabled लोगों को employment देती हैं तथा जो working campuses हैं, offices हैं, वे जो facilities मुहैया कराते है, मैं समझता हूं कि वे अपने employees की देखरेख में, उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में और उनके overall personality development के मामले में दुनिया में लगभग बराबरी पर आते हैं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : सभापति जी, मैं नौजवान मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी सवाल यह है कि Information & Technology Industry के employees चाहे प्राइवेट हों या सरकारी, उनकी health पर बहुत असर पड़ता है। 53 per cent workers are affected with depression, severe headache, obesity, chronic backache, spondylitis, diabetes and hypertension. उनके बीमार होने पर और रिटायर होने के बाद क्या इंडस्ट्री वाले उनको कुछ benefit देते हैं या नहीं, यदि हां, तो क्या benefit दिया जाता है, अगर नहीं तो, क्या सरकार की ओर से इन affected employees की मदद के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है या नहीं?

SHRI SACHIN PILOT : Mr. Chairman, Sir, the working conditions of the BPO companies are regulated by the provisions of the Shops and Estabilshments Act of the respective State Governments. Therefore, the working hours, working provisions, etc., etc., are enacted and implemented by the State Governments. जहां तक माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है कि जो work-related disorders हैं, जो stress-related disorders हैं, उनमें से काफी life-style related भी हैं और जैसे भारत में आधुनिकीकरण हुआ है, हमारी वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास हुआ है, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है, उसके चलते जो नई-नई बीमारियां हैं, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, इनके बारे में नाना प्रकार की reports हमारे पास भी आती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें self-regulation की जरूरत है। जहां तक कंपनियों का सवाल है, मैं समझता हूं कि कंपनियां भी चाहती है कि वे employees की health में निवेश करें, investment करें, ताकि उनके employees और productive रहें। उन्होंने यह पूछा कि सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार का इसमें dirctly कोई interference नहीं है, लेकिन हम हमेशा IT Sector से और अलग-अलग कंपनियों के लोगों से संवाद रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो नौजवान workforce है, वह मजबूत हो और अपने अंदर हुनर पैदा करे और जितने ज्यादा हमारे employees productive होंगे, हमारे IT Sector को उतनी ही ज्यादा बढ़ोत्तरी मिलेगी।

MS. MABEL REBELLO: Part (c) of the question says that 54 per cent of the people are suffering from chronic and life style related diseases. I would like to know from the hon. Minister whether these IT-enabled institutions, where a large number of people are working at night, offer services of professional counsellors and psychiatrists to their employees to deal with their problems. Then, has the Government ever conducted any study to find out what are the repercussions on these employees, who are working for months together in night shift, due to their working conditions? of they have not conducted any study so far, do they have the intention and the machinery to conduct any such study in future?

SHRI A. RAJA: Sir, as has already been explained by my colleague, there is no conclusive proof or inference that has been drawn either by the Health Ministry or by the Labour Ministry that people are suffering from chronic diseases because of the IT and BPO industry. In spite of that, the Government often gives directions on what the regulations should be. But, I must be very clear before the House that the survey, that has been allegedly conducted by a private organisation. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Leave aside the private agency, have you ever conducted a study?

SHRI A. RAJA: The Health Ministry has conducted a study. After that study, it has been disclosed in this Parliament itself that there is no conclusive evidence of chronic diseases because of life style of the "people working in the IT industry. There is no such scientific inference that has been drawn either by the Labour Ministry or by the Health Ministry. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, don't interrupt.

SHRJ A. RAJA: So, when there is no proof, or, conclusive evidence at all to say that these people suffer from chronic diseases, the Government cannot react. But, I must submit that the alleged survey by a particular association was conducted only on 54 persons. When two million people are working in the IT and BPO sector, only 54 persons were taken for random survey. And, out of that survey, it has been disclosed that 54 per cent suffered from chronic diseases, which cannot be acceptable scientifically and medically.

MS. MABEL REBELLO : Forget about this survey. He has not answered my question. I asked whether the Government intended to conduct any serious scientific study on this issue.

श्री अमर सिंह : सभापति महोदय, हमारे नौजवान मंत्री ने प्रश्नोत्तर के बीच में एक बात कही कि इस सेक्टर में तीस प्रतिशता महिलाएं काम करती हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि काश, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार यहां पर नाइट ड्यूटी भी होती है। हमें यह सूचना मिली है कि कई बार ये खबरें भी प्रकाशित होती हैं कि महिलाओं के साथ कई बार खराब आचरण भी हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में कोई विशेष नियमावली या दिशा-निर्देश इन आईटी कंपनियों को दिए गए हैं? किसी सेक्टर में महिलाओं के तीस प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। महिलाओं के सम्मान के लिए या महिलाओं को काम करते समय उनकी मर्यादा की सुरक्षा संरक्षण हो सके, इसके बारे में आपने कोई प्रावधान किया है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इन आईटी कंपनियों को कोई दिशा-निर्देश संप्रेषित किए हैं?

श्री सचिन पायलट : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूं, क्योंकि माननीय सदस्य खुद महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े वकील हैं और यह भी चाहते हैं कि महिलाएं बढ़-चढ़कर आईटी सेक्टर में भाग लें। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें लगभग एक तिहाई employees महिलाएं हैं। किसी और सेक्टर में इतनी ज्यादा महिलाएं काम नहीं करती हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरान्वित महसूस करने की बात है। जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है, यह निश्चित तौर पर, प्राइवेट कंपनियां या किसी और सेक्टर की, उनकी जिम्मेदारी होती है और law and order स्टेट गवर्नमेंट का विषय तो है है, लेकिन हमारा मंत्रालय भी निरंतर उनके साथ संपर्क में रहता है। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसे वातावरण में महिलाओं को काम करने का मौका मिले कि वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। वे न सिर्फ अपने आपको उपयोगी बनाएं, बल्कि एक ऐसा उदाहरण पैदा करें कि अगर महिलाएं आईटी सेक्टर में काम कर सकती हैं, तो वे अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सकती हैं। जहां तक औपचारिक निर्देश की बात है, तो यह हमारे दायरे में नहीं आता है।

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, let the Minister read the answer that he has given. I am asking the Senior Minister. The answer says, "There have been a few reports about incidence of life style-

related diseases....". That means, you are assertive enough, affirmative enough. For him to say that there has never been a case is something, Mr. Chairman, for you to look into.

Sir, he has said, 'alleged survey'. Nobody made allegations here his own written answer said. He did not allege it. What should have been said was reported survey' - perhaps it has been – a 'reported survey'. Let him correct the words. I would like to put a simple question. Other hon. Members have also said about the thirty per cent women employees, throughout the night working, and round-the-clock working etc. This answer says, "As per the Ministry of Labour and Employment, the working conditions in the BPO companies are largely regulated by the provisions of the Shops and Establishments Act of the respective State Governments." Sir, firstly, the Shops and Establishments Act talks about the working hours; secondly, the Shops and Establishments Act talks about the round-the-clock working hours; thirdly, the Shops and Establishments Act talks its fall out on the health; fourthly, it talks about two holidays for round-the-clock working; and, fifthly, it also talks about the wages - double or three times. But these provisions differ from State to State. What is the Central Government now trying to do? Are you thinking of bringing in new provisions, new Act for round-the-clock working? Or, are you thinking of, as another Member said, setting up machinery to look into the health aspects or the fall out on the health? You have 24-hours-working a day by a lady, and, you are saying that there has never been a survey. There is something called common sense, which is there in everybody; even if there is no survey, I can imagine the effects of sitting for 24-hours, and sometimes, it does happen. I know a BPO company where they work continuously for two to three days, which means, 48 to 72 hours. What will be the after-effects? Sir, the survey is not necessary, only common sense is necessary to tell us as to what will happen?

SHRI A. RAJA: Sir, all the statues, which are available in the country under the Ministry of Labour, are applicable to the industry also. If the hon. Member wants any specific area to be dealt with by the separate legislation or the exclusive legislation, it can be discussed and it is open to the hon. Members to give suggestions in that regard. We can discuss it with the concerned Ministries. We have no problem at all. But, at the same time, we cannot say that the people are forced. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please don't intervene.

SHRI A. RAJA: Unless the specific issues are brought to the notice of the Minister or the Ministry, we cannot take suo motu action in this regard. So far as the survey is concerned, for the sake of the hon. Member, I can correct myself but whether it is 'allegedly' or 'reportedly', I want to reiterate that even in the survey only 36 people were taken into account, and, out of that, it has been highlighted that 54 per cent people suffering from chronic diseases like spondylitis or other problems.

When it was referred to the Ministry of Health and the Ministry of Labour, the Health Ministry– which also conducts other surveys for other diseases including major diseases – was very categorical and is very categorical that this type of scientific and medical inference which has been drawn 'reportedly'–I correct myself –cannot have a conclusive proof and it cannot be withstood.